

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7

देहरादून: दिनांक 30 दिसम्बर, 2016

विषय: राज्य सरकार के कार्मिकों, स्थानीय निकायों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, राजकीय विश्वविद्यालयों तथा प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के कार्मिकों, जिन्हें सातवें पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किये गये हैं, को अनुमन्य मंहगाई भत्तों की दरों का निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या-1/2/2016-ई.॥(बी) दिनांक 04 नवम्बर, 2016 के क्रम में राज्य सरकार के सरकारी सेवकों को, जिन्हें सातवें पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य है, को दिनांक 01 जुलाई, 2016 से 02 प्रतिशत मंहगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- पूर्व वेतनमान/ग्रेड वेतन हेतु दिनांक 01 जनवरी, 2016 से स्वीकृत मंहगाई भत्ता नये वेतन में सम्मिलित होने के कारण नयी वेतन संरचना (वेतन मैट्रिक्स) में मंहगाई भत्ता दिनांक 01 जनवरी, 2016 से 30 जून, 2016 तक शून्य रहेगा।

3- शासकीय संकल्प संख्या-289/XXVII(7)50(16)/2016 दिनांक 27 दिसम्बर, 2016 द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य के सभी श्रेणी के कर्मचारियों को वर्तमान में उन्हें प्राप्त विभिन्न प्रकार के भत्तों (मंहगाई भत्ते को छोड़कर) एवं सुविधाओं की कुल धनराशि को पुनरीक्षित वेतन संरचना (वेतन मैट्रिक्स) में भी अग्रिम आदेशों तक यथावत् रखा जाय।

4- शासनादेश संख्या-1-1599/ दस-42 (एम)/97, 23, नवम्बर, 1988 के प्रस्तर-3, 4, 5 एवं 07 में उल्लिखित शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू होंगे।

5- पुनरीक्षित मंहगाई भत्ते का भुगतान पूर्व निर्धारित शर्तों के अधीन किया जायेगा।

6- उक्त वर्णित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन उपरोक्तानुसार स्वीकृत मंहगाई भत्ता अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी अनुमन्य होगा।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)

सचिव।